



चैत्र नवरात्र

प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री



नवरात्र पूजन के पहले दिन कलश पूजन के साथ मां शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया है। मां शैलपुत्री एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल का पुष्प लिए हुए हैं। इनका वाहन वृषभ है। भक्तों में मां शैलपुत्री का महत्व और आराधना विशेष रूप से है। इनकी पूजा से परिवार में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। इनकी पूजा से मानसिक तनाव दूर होता है। शैलपुत्री का पूजन करने से 'मूलधार चक्र' जागृत होता है। शैलपुत्री का पूजन करने से जीवन में स्थिरता और रिश्तों में मजबूती आती है, जिससे परिवार में सौहार्द एवं प्रेम बढ़ता है। साधक इस दिन केसरिया वस्त्र पहनते हैं। मनोविकारों से बचने के लिए मां को सफेद कनेर का फूल चढ़ाते हैं।

मंत्र : या देवी सर्वतोभू मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता । नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ॥

न्यूज शॉर्ट्स

असम कांग्रेस के सांसद बोरदोलोई भाजपा में शामिल

एजेंसी, गुवाहाटी। असम के कंगोस से लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और असम भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया की मौजूदगी में यह औपचारिकता पूरी हुई। बोरदोलोई ने यह आकांक्षित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा, जिसमें उन्होंने सभी पदों, विधायकियों और सदस्यता से अपने इस्तीफे की जानकारी दी। यह कदम राज्य में 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। (अनंत ज्ञान)

आदि कैलाश यात्रा 1 मई से होगी शुरू

एजेंसी, पिथौरागढ़। एक मई से आदि कैलाश यात्रा शुरू हो जाएगी, जब शिव-पार्वती मंदिर के कपाट खुलेंगे। 14,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस पावन धाम के द्वार खुलना यात्रा के औपचारिक शुभारंभ का प्रतीक है। ग्रामीणों का शीतकालीन प्रवास समाप्त होकर सीमांत गांवों में वापसी का सिलसिला भी शुरू होगा। ग्राम प्रधान कगेंद्र सिंह कुटियाल और पुजारियों ने व्यवस्थाओं पर बैठक कर कपाट खोलने का निर्णय लिया। श्रद्धालु आदि कैलाश और पार्वती सरोवर के दर्शन व पूजन कर सकेंगे। (अनंत ज्ञान)

अंदर के पन्नों पर पढ़ें

- ▶▶ **प्रदेश में तीआड़ी कल्चर पर सर्किटल वार** - पृष्ठ 2
- ▶▶ **शिक्षा की गुणवत्ता में हो रहा सुधार: आरएस बाली** - पृष्ठ 5
- ▶▶ **27 घंटे बाद बवाल हुआ पठनकोट एनएच** - पृष्ठ 7
- ▶▶ **छह दिन बाद गुमनाम महिला सुरक्षित बरामद, पति के सुपुर्द** - पृष्ठ 9
- ▶▶ **बस कितना बढ़ तो बुर्जुा को पारल करने की कोशिश** - पृष्ठ 13

वेनेजुएला-ईरान के बाद क्यूबा पर हमला कर सकता है अमेरिका

एजेंसी, वॉशिंगटन

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वह 'क्यूबा को अपने कब्जे में लेने' का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा कि किसी न किसी रूप में क्यूबा को लूना... चाहे मैं उसे आजाद करूँ या अपने नियंत्रण में ले लूँ। मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ।

न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप के इस बयान को काफी चैंकाने वाला माना जा रहा है। अमेरिका के इतिहास में कई राष्ट्रपति क्यूबा के साथ तनावपूर्ण रिश्तों में रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस तरह खुले तौर पर क्यूबा पर कब्जा करने की बात नहीं कही थी। इस साल ट्रंप पहले ही वेनेजुएला और ईरान में सैन्य

बजट सत्र

दूसरे चरण के पहले दिन विधानसभा में सेवा विस्तार पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आर-पार

संदिग्ध व भ्रष्टाचार में लिप्त अफसरों की होगी छुट्टी: सीएम सुक्खू

अनंत ज्ञान

सत्यदेव भारद्वाज, शिमला। सुखविंद सिंह सुक्खू सरकार ने संवेदनशील पदों पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन प्रश्नकाल के दौरान घोषणा की है कि ऑफिसर्स ऑफ़ डायटफुल इंटीग्रिटी (ओडीआई) सूची में शामिल ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को तुरंत उनके पदों से हटाया जा रहा है। इसके साथ ही, जिन लोगों को सेवा विस्तार (एक्सटेंशन) के बाद संवेदनशील पदों पर तैनाती दी गई है, उनकी सेवाएं भी तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।

यह मामला उस समय उठा जब ऊना के विधायक सतपाल सिंह सती ने अपने क्षेत्र से जुड़ा मुद्दा विधानसभा में उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तहसीलदार, जो रिश्तवत के मामले में पकड़ा गया था, उसे सरकार ने सेवा विस्तार देकर फिर से तैनात कर दिया। उन्होंने कहा कि इसको लेकर स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे



मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुक्खू सदन में अपनी सरकार का पक्ष रखते हुए।

अनंत ज्ञान

हैं और आरोप लगा रहे हैं कि प्रभावशाली लोगों के दबाव में ऐसी नियुक्तियों की जा रही हैं, जिनके जरिए जमीनों के मामले प्रभावित हो रहे हैं।

इस पर मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में बताया कि फिलहाल ओडीआई सूची में शामिल तीन अधिकारी संवेदनशील पदों पर तैनात पाए गए हैं और सरकार ने उनकी सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया है। इनमें विजय कुमार राय, तहसीलदार युद्धवीर सिंह

विधायक सती के सवाल पर ओडीआई सूची पर सख्त हुई सुक्खू सरकार

ठाकुर (ओएसडी) और राय बहादुर सिंह नेगी शामिल हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि पिछले दो वर्षों में दो कर्मचारी ओडीआई सूची से बाहर भी आए हैं, जिनमें महेंद्र लाल (वरिष्ठ सहायक) और राय बहादुर नेगी (रीडर) शामिल हैं। वहीं, इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष

जयराम ठाकुर ने भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकार से ओडीआई सूची मांगी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने सदन में केवल तीन नामों का ही जिक्र किया है। उन्होंने पूछा कि क्या यही सूची अदालत में पेश की जाएगी या इसमें और नाम भी शामिल हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पास फिलहाल पूरी जानकारी नहीं है। 2025 तक के फैसलों की समीक्षा नाम हैं तो वे सरकार को दें, उन

हिमाचल के 12 आईएस 5 राज्यों के विस चुनाव में बनाए चुनाव पर्यवेक्षक

अनंत ज्ञान, शिमला। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश के 12 आईएस अधिकारियों को चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने इनके विभागों का अतिरिक्त कार्यभार 9 अन्य अफसरों को सौंपा है। 2004 बैच की प्रियंका बासु इंग्टी, सचिव पशुपालन रितेश चौहान, डायरेक्टर ऊर्जा राकेश कुमार प्रजापति, विशेष सचिव सेवाएं हरिकेश मीना, डायरेक्टर ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज राघव शर्मा सहित अन्य अफसरों की ड्यूटी चुनाव में लगी है। इसके अलावा डीसी नेगी को डायरेक्टर परिवहन विभाग, आईएसएस आशीष सिंहमार को सचिव पशुपालन, आबिद हुसैन सादिक को डायरेक्टर ऊर्जा और तोरुल एस रविश को डिजिटल तकनीक एवं एचआरटीसी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अन्य आईएसएस अधिकारियों को भी स्वास्थ्य, ऊर्जा और ग्रामीण विकास जैसे विभागों का अतिरिक्त जिम्मा दिया गया है।

हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड जारी

अनंत ज्ञान

सत्यदेव भारद्वाज, शिमला। हिमाचल सरकार ने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड और सोशल मीडिया

सुक्खू सरकार ने जींस टीशर्ट पर लगाई रोक

कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय में साफ-सुथरे, शालीन और औपचारिक कपड़े पहनना अनिवार्य होगा। पुरुष कर्मचारियों को शर्ट-पैंट और महिला कर्मचारियों को साड़ी, सूट या अन्य औपचारिक

परिधान पहनने के निर्देश दिए गए हैं। जींस और टी-शर्ट जैसे अनौपचारिक कपड़ों से परहेज करने को कहा गया है।

सरकार ने अपने आदेश कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को हमेशा औपचारिक, साफ-सुथरे और सादे रंगों के कपड़े पहनने चाहिए। कोर्ट में पेशी या कार्यालय में उपस्थित के दौरान केजुअल या पार्टी वियर से पूरी तरह परहेज करना होगा। आदेश में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी का पहनावा उसके पेशेवर व्यवहार और कार्यस्थल की गरिमा को दर्शाता है।

सोशल मीडिया पर अनुशासन बनाए रखने के लिए निर्देश

सीएम सुक्खू ने कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट से सरकारी नीतियों, फैसलों या राजनीतिक/धार्मिक विषयों पर टिप्पणी नहीं करेगा। साथ ही, बिना अनुमति किसी भी आधिकारिक जानकारी को सार्वजनिक करने पर रोक लगाई गई है। वहीं, कार्मिक विभाग के निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बिना अनुमति कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी आधिकारिक दस्तावेज या जानकारी को सार्वजनिक नहीं करेगा। यदि कोई कर्मचारी किसी सार्वजनिक मंच या मीडिया में अपनी राय रखता है तो उसे यह स्पष्ट करना होगा कि यह उसके निजी विचार हैं, सरकार के नहीं। सरकार ने चेतावनी दी है कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को भी अपने अधीन कर्मचारियों में इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

इंदौर में कार चार्जिंग करते समय घर में लगी आग, आठ की गई जान

एजेंसी, इंदौर

इंदौर में इलेक्ट्रिक कार टाटा पंच में चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिसने तीन मंजिला मकान को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में कारोबारी मनोज पुगलिया, उनकी गर्भवती बहू सिमरन सहित 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हैं। मारे गए लोगों में से 6

मनो के रिश्तेदार थे, जो मंगलवार को बिहार के किशनगंज से आए थे। घटना बुधवार तड़के 3.30 से 4 बजे के बीच बंगाली चौराहे के पास ग्रेटर बृजेश्वरी कॉलोनी की है।

पुलिस के अनुसार, आग ने घर के अंदर रखे गैस सिलेंडरों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे एक के बाद एक सिलेंडर फटने लगे। धमाका इतना तेज था कि मकान का एक हिस्सा ढह गया। घर में लगे



डिजिटल लॉक खुल नहीं पाए, इसके कारण अंदर सो रहे लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। शहरवासियों ने बताया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सूचना देने के करीब एक घंटे बाद मौके पर पहुंचीं। परिवार ने तिलकनगर मुक्तिधाम में शवों का अंतिम संस्कार किया।

वहीं, पीएम मोदी ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। उन्होंने मृतकों के परिजन को 2-2 लाख और घायलों को 50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। (अनंत ज्ञान)

दिल्ली में 4 मंजिला इमारत में लगी आग एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत

एजेंसी, नई दिल्ली

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के साथ नगर, पालम इलाके में बुधवार को चार मंजिला इमारत में आग लग गई। आग की इस घटना में 3 बच्चों समेत एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग अस्पताल में भर्ती हैं।

जानकारी के अनुसार, आग लगने के बाद इमारत के अंदर एक ही परिवार के लोग फंस गए थे। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस और एंबुलेंस की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और राहत-बचाव अभियान शुरू किया गया।

आग लगने की वजह नीचे भूजल पर शॉर्ट सर्किट होना माना जा रहा है। नीचे की मंजिलों से ही आग ऊपर के मंजिलों में पहुंची और परिवार फंस गया। भूजल पर परिवार की



कॉस्मेटिक एवं कपड़ों की दुकानें हैं, जबकि ऊपर की मंजिलों में परिवार रहता है। अधिकारियों के अनुसार हादसे में घायल हुए तीन बच्चों को पालम स्थित दिव्य प्रस्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। मौके पर तीन एंबुलेंस तैनात की गई थीं, जबकि अन्य एंबुलेंस संकरी और भीड़भाड़ वाली जगह के कारण कुछ दूरी पर खड़ी रहीं। (अनंत ज्ञान)

चिट्ठा मामले में नवविवाहित दंपती अदालत में पेश

अनंत ज्ञान

सुंदरनगर। जिला मंडी के सुंदरनगर में चिट्ठा बरामदगी मामले में गिरफ्तार नवविवाहित दंपती को बुधवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच तेज करते हुए नशे की खेप के श्रोत और इसके संभावित नेटवर्क की पड़ताल शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि सुंदरनगर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत मंगलवार शाम बस अड्डा क्षेत्र के एक निजी होटल में दबिश देकर मंडी के जेल रोड निवासी युवक और कांगड़ा के दंग क्षेत्र की युवती को 21.017 ग्राम हेरोइन सहित

तीन दिन पहले किया था प्रेम विवाह, सुंदरनगर होटल से हुई थी गिरफ्तारी

गिरफ्तार किया था। दोनों ने महज तीन दिन पहले ही प्रेम विवाह किया था और होटल के कमरे में ठहरे हुए थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक नियमित रूप से क्षेत्र की एक कुख्यात महिला नशा तस्कर का बेटा है, जिससे मामले को और गंभीरता से लिया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि नशे की खेप कहां से लाई गई थी और इसे आगे कहां पहुंचाया जाना था।

डोनाल्ड ट्रंप बोले- क्यूबा को हासिल करके रहूंगा, 65 साल से है दोनों देशों में विवाद

कार्रवाई कर चुके हैं। ऐसे में उनके बयान को सिर्फ मजाक या अचानक कही गई बात नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एक संभावित अगला कदम समझा जा रहा है। अमेरिका और क्यूबा के संबंध 65 साल से खराब चल रहे हैं। ट्रंप ने इससे पहले रिवार को एयर फोर्स वन में भी कहा था कि मैं क्यूबा को संभाल रहा हूँ, जल्द ही हम कोई डील करेंगे या जो करना होगा करेंगे। उन्होंने यह भी साफ किया कि उनकी प्राथमिकता पहले ईरान, उसके बाद क्यूबा है। (अनंत ज्ञान)

एजेंसी, नई दिल्ली

राज्यसभा में बुधवार को एक भावुक और गरिमायुक्त माहौल देखने को मिला, जब अप्रैल से जुलाई के बीच सेवानिवृत्त होने जा रहे 59 सांसदों को औपचारिक विदाई दी गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद की भूमिका, वरिष्ठ नेताओं के योगदान और लोकतांत्रिक परंपराओं की अहमियत पर विस्तार से बात की। विदाई पाने वाले प्रमुख नेताओं में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता रामदास आठवले शामिल रहे। हालांकि, शरद पवार और रामदास आठवले दोबारा राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं।

सेवानिवृत्ति पीएम बोले- संसद एक ओपन यूनिवर्सिटी, राजनीति में कभी फुल स्टॉप नहीं

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में संसद को 'ओपन यूनिवर्सिटी' बताते हुए कहा कि यहां हर दिन सोखने और सिखाने का अवसर मिलता है। संसद में होने वाली बहसें, चर्चाएं और विचार-विमर्श लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। उन्होंने कहा कि यह सदन एक ऐसा मंच है जहां विभिन्न विषयों पर चर्चा होती है, अलग-अलग विचार सामने आते हैं और हर सदस्य का योगदान महत्वपूर्ण होता है। पीएम ने एक महत्वपूर्ण संदेश देते हुए कहा कि राजनीति में कभी पूर्ण विराम नहीं होता। उन्होंने विदा हो रहे सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि उनका अनुभव



और योगदान हमेशा देश के काम आएगा। उन्होंने कहा, भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। कुछ लोग फिर से सदन में लौट सकते हैं, तो कुछ सामाजिक जीवन में अपने अनुभव का उपयोग करेंगे। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जो नेता अब संसदों से दलीय राजनीति से ऊपर उठकर एक-दूसरे का सम्मान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की अस्थी ताकत आपसी सम्मान और संवाद में है।

जब विदाई का समय आता है, तो हम सब पार्टी की भावना से ऊपर उठकर एक समान भाव से अपने साथियों के योगदान को याद करते हैं। वरिष्ठ नेताओं के योगदान की सराहना पीएम मोदी ने अपने भाषण में कई वरिष्ठ नेताओं का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और शरद पवार को सराहना करते हुए कहा कि इन नेताओं ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा सार्वजनिक सेवा और संसदीय कार्य में समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि नए सांसदों को इन अनुभवों नेताओं से सीखना चाहिए और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाना चाहिए। (अनंत ज्ञान)

खड़गे मजाकिया अंदाज में देवगौड़ा से बोले- प्रेम हमसे, शादी मोदी से

इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने भी अपने अंदाज में माहौल को हल्का किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का जिक्र करते हुए मजाकिया लहजे में कहा कि 'मुझे नहीं पता क्या हुआ, उन्होंने मुहूर्त हमारे साथ देखा, लेकिन शादी मोदीजी के साथ कर ली।' खरगे के इस बयान पर सदन में हल्की हंसी भी देखने को मिली। उन्होंने यह भी कहा कि शरद पवार जैसे नेता दोबारा सदन में लौटेंगे और अपनी सक्रिय भूमिका जारी रखेंगे।

राजधानी में महंगाई की मार के बीच भक्ति का उजाला

नवरात्र को लेकर मंदिरों में सजी आस्था की चौकियां, मां के आगमन की आहट, शहर में भक्तिमय माहौल

अनंत ज्ञान

सत्यदेव भारद्वाज, शिमला। शहर-ए-शिमला में आस्था की फिजा फिर से महक उठी है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व 19 मार्च से शुरू हो रहा है। मंदिरों में रंग-बिरंगी रोशनी, फूलों की सजावट और भक्ति गीतों की गुंज के बीच मां दुर्गा के स्वामित्व की तैयारियां अपना शबाब पर हैं। यह पर्व न केवल देवी आराधना का प्रतीक है, बल्कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत का भी शुभ संकेत लेकर आता है, जिससे श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है।

इस बार नवरात्रि की शुरुआत विशेष शुभ योगों के संयोग में हो रही है, जिससे



इसका धार्मिक महत्व और बढ़ गया है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा

के साथ चटस्थापना की जाएगी। इसके लिए सुबह 6:54 से 7:58

बजे तक पहला शुभ मुहूर्त और दोपहर 12:05 से 12:53 बजे तक

चलाई जाएंगी विशेष बसें

शहर के प्रमुख मंदिरों में सुबह छह बजे से ही कपाट खुल जाएंगे और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के साथ-साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष बस सेवाएं भी चलाई जाएंगी, खासकर तापदेवी मंदिर के लिए। कालोबाड़ी और अन्य मंदिरों में भी सुबह से ही पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। नवरात्रि के इन नौ दिनों में भक्ति, संयम और श्रद्धा का जो संगम देखने को मिलता है, वह हर दिल को सुकून देता है। महंगाई और संसाधनों की चुनौतियों के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई है। यही वजह है कि हर साल की तरह इस बार भी शिमला देवीमय रां में रंगने को तैयार है, जहां हर गली, हर मंदिर और हर दिल में मां दुर्गा का वास महसूस होगा।

अभिजीत मुहूर्त रहेगा। ज्योतिषीय दृष्टि से राजयोग, सर्वार्थ सिद्धि योग और ब्रह्म योग का संगम इस नवरात्र को अत्यंत मंगलकारी बना रहा है। हालांकि, इस बार आस्था के इस पर्व पर महंगाई की हल्की परछाईं भी पड़ती नजर आ रही है। व्यावसायिक गैस सिलिंडरों की किल्लत और बढ़ती कीमतों ने मंदिरों में होने वाले भंडारों की व्यवस्था को प्रभावित किया है। कई प्रमुख मंदिरों में अब लकड़ी और भीजल भट्टियों का सहारा लिया जा रहा है, ताकि भक्तों के प्रसाद और भंडारे में कोई कमी न आए। यह बदलाव जहां प्रबंधन के लिए चुनौती है, वहीं श्रद्धालुओं की सेवा भावना इसे सहज बना रही है।

न्यूज ब्रीफ

विनय कुमार ने नवरात्र पर दी शुभकामनाएं

अनंत ज्ञान ब्यूरो, शिमला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा है



कि नवरात्र का पर्व केवल पूजा-अर्चना का ही नहीं, बल्कि आरम्भिक शुद्धि, अनुशासन और आदर्श जीवन मूल्यों को अपनाने का संदेश भी देता है। उन्होंने कहा कि नौ दिनों तक देवी के विभिन्न स्वरूपों की आराधना करते हुए मनुष्य अपने भीतर श्रद्धा, संयम और धर्म के प्रति आस्था को प्रबल करता है, जो जीवन को सही दिशा देने में सहायक होती है। विनय कुमार ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे इस पावन अवसर पर समाज में सद्भाव, भाईचारा और संकरात्मकता को बढ़ावा दें तथा अपने आचरण और विचारों में पवित्रता लाकर एक बेहतर समाज के निर्माण में योगदान दें।

पंचायत समिति मशोबरा में 15 वार्ड निर्धारित

अनंत ज्ञान ब्यूरो, शिमला। पंचायत समिति मशोबरा के वार्ड नंबर सात (पीरन) के परिसीमन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। खंड विकास अधिकारी मशोबरा अंकित कोटिया ने प्रस्तावना आमजन के अवलोकन के लिए सार्वजनिक करते हुए कहा है कि इस संबंध में कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्तियां, दावे अथवा सुझाव तीन दिव के भीतर खंड विकास अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। अधिसूचना के अनुसार पंचायत समिति मशोबरा में कुल 15 वार्ड निर्धारित किए गए हैं, जिनमें प्रत्येक वार्ड में दो या तीन पंचायतों को शामिल किया गया है। इनमें गुम्मा, बलदेवां, मशोबरा, मूलकोटी, ढल्लू, दरभोग, पीरन, कोटी, जनेडघाट, चमियाणा, मल्थाणा, पुजारल्ली, भौट और नालदेहरा सहित विभिन्न वार्डों की संरचना तय की गई है।

आंगनवाड़ी केंद्र में सजा बचपन का रंगीन संसार

अनंत ज्ञान ब्यूरो, शिमला। शिमला के कैथु स्थित मेफ्रील्ड स्कूल के आंगनवाड़ी केंद्र में रोटीय क्लब शिमला के रोटीय पार्लरन ने 'हेप्पी स्कूल्स' परियोजना के तहत एक सुसज्जित टॉय रूम स्थापित किया। इस पहल ने बच्चों के सीखने और खेलने के अंदाज को नई रौनक दी है। टॉय रूम में रंग-बिरंगे खिलौने, रचनात्मक खेल सामग्री और आरामदायक प्लेयर मेट्स रखे गए हैं, जो बच्चों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करते हैं। अध्यक्ष अंकिता बंबा और सान्या गोयल ने बिल्डिंग ब्लॉक्स, स्नाइड, रंग और अन्य शिक्षाप्रद सामग्री भेंट की। इन संसाधनों से बच्चों की कल्पनाशक्ति, मानसिक और शारीरिक विकास को मजबूती मिलेगी। उपस्थित लोगों ने इसे समाज और बच्चों के उज्वल भविष्य के लिए प्रेरक कदम बताया, जो शिक्षा को अनंदमय बनाता है।

मेहनत और आत्मविश्वास का दिया संदेश

अनंत ज्ञान ब्यूरो, शिमला। शिमला के राजकीय कन्या महाविद्यालय में स्वातक अंतिम वर्ष की छात्राओं के लिए दिवाई समारोह 'उड़ान' बेहद खूबसूरत और जज्बाली अंदाज में आयोजित किया गया। महाविद्यालय्य सभाकारों ने प्राचार्य अतुरिता सक्सेना, पीटीए प्रतिनिधियों, प्राध्यापकों और छात्राओं ने बड़-चढ़कर भाग लिया। समारोह में विरिष्ट छात्राओं की शैक्षणिक उपलब्धियों और महाविद्यालय में उनके योगदान को याद किया गया, जिससे आत्मीय माहौल बना। जुनियर छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, मॉडलिंग और मनोरंजक गतिविधियों के जरिए अपनी सौंदर्य के प्रति सम्मान और मोहब्बत जताई। प्राचार्य ने जीवन के अगले पड़ाव के लिए मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास का संदेश दिया। कार्यक्रम का समापन सामूहिक भोज के साथ हुआ, जिसमें सभी ने मिलकर यादों के इस खूबसूरत सफर को संजोया।

नि:शुल्क कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू

अनंत ज्ञान ब्यूरो, शिमला। शिमला में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के लिए प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अनुदान योजना के तहत नि:शुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। नीरट्टि शिमला के सहयोग से दो कोर्स संचालित किए जाएंगे- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी और ऑफिस ऑटोमेशन, अकाउंटिंग एवं फिन्सिंसिग अडिस्ट्रेट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स तीन माह का होगा, प्रतिदिन दो घंटे प्रशिक्षण के साथ, जबकि दूसरे कोर्स की अवधि तीन माह और प्रतिदिन चार घंटे निर्धारित है। आवेदक का अनुसूचित जाति वर्ग का होना और हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। चयन मेरिट और दस्तावेज सत्यापन पर होगा। प्रशिक्षण में 85% उपस्थिति पर प्रतिमाह 2000 रुपए का मानदेय मिलेगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए 30% सीट आरक्षित है और जिला शिमला के लिए कुल 50 सीटें निर्धारित की गई हैं।

शिमला विवि परिसर में नवीनीकृत उपडाकघर शुरू, अब एक छत के नीचे मिलेंगी सभी सेवाएं

अनंत ज्ञान

ब्यूरो, शिमला। शिमला डाक मंडल के तहत प्रदेश विश्वविद्यालय परिसर स्थित समरहिल उपडाकघर को एन-जेन नेक्स्ट जेनरेशन पहल के तहत नवीनीकृत कर मंगलवार को लोकार्पित किया गया। इस आधुनिक डाकघर का उद्घाटन मुख्य पोस्टमास्टर जनरल संजय सिंह और विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. महावीर सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर निदेशक डाक सेवाएं हरजिंदर सिंह भट्टी, प्रवर अधीक्षक कंचन सिंह चौहान, उप अधीक्षक देव राज सहित छात्र, मांडिया प्रतिनिधि और डाक विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे। यह पहल शैक्षणिक समुदाय को नागरिक-हितैषी और तकनीक-सक्षम सेवाएं सुलभ कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल संजय सिंह ने बताया कि 'एन-जेन' पहल के तहत पहले चरण में देशभर में 46 डाकघरों का आधुनिकीकरण



समरहिल उपडाकघर का लोकार्पण करते अधिकारी। **अनंत ज्ञान**

◆ एन-जेन पहल के तहत समरहिल उपडाकघर अपग्रेड छात्रों को मिलेगा बड़ा लाभ

किया जा चुका है, जबकि दूसरे चरण में 80 डाकघरों को उन्नत किया जा रहा है, जिनमें समरहिल और नौपी उपडाकघर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह नई व्यवस्था ग्राहक-हितैषी, डिजिटल रूप से

सशक्त और एक ही छत के नीचे बचत योजनाएं, बीमा, डाक-पार्सल सेवाएं तथा ई-सेवाएं प्रदान करेगी। कुलपति डॉ. महावीर सिंह ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को परिसर में ही सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध होंगी। यह कदम डाक विभाग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच तालमेल को भी मजबूत करेगा।

कांग्रेस सरकार के संरक्षण में फल-फूल रहा गुंडाराज : कपूर

अनंत ज्ञान ब्यूरो, शिमला। भाजपा के प्रदेश वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक कपूर ने नालागढ़ में दिनदहाड़े हुई फायरिंग की घटना को लेकर कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और अपराधियों के हासले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में भी खुलेआम फायरिंग जैसी घटनाएं हो रही हैं, जिससे आम जनता में भय का माहौल बन गया है।



त्रिलोक कपूर ने आरोप लगाया कि यह घटना कोई अपवाद नहीं बल्कि प्रदेश में बढ़ते अपराधों की श्रृंखला का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सरकार की दलीला चर्याप्रणाली और प्रशासनिक निष्क्रियता के कारण असामाजिक तत्वों को खुली छूट मिल रही है। उन्होंने मांग की कि मामले में सख्त कार्रवाई कर कानून व्यवस्था बहाल की जाए, अन्यथा भाजपा इस मुद्दे को सड़कों से लेकर सदन तक जोर-शोर से उठाएगी।

बदलाव प्रदेश सरकार के कैबिनेट रैंक वापसी के फैसले का दिखने लगा असर प्रदेश में वीडाईपी कल्चर पर सर्जिकल वार

अनंत ज्ञान

सत्यदेव भारद्वाज, शिमला। प्रदेश सरकार ने कैबिनेट रैंक व उससे जुड़ी तमाम शानो-शौकत वापस लेने के फैसले का असर अब प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। एक दिन बाद ही इस निर्णय ने सत्ता के तौर-तरीकों में बदलाव की बुनियाद रख दी है, जहां सादगी, जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन को प्राथमिकता मिलती नजर आ रही है।

सरकार के इस कदम का सबसे बड़ा असर उन नेताओं और पदाधिकारियों पर पड़ा है, जो अब तक मंत्री स्तर की सुविधाओं का लाभ उठा रहे थे। नरेश चौहान और सुनील कुमार बिट्टू जैसे सलाहकारों से लेकर नंदलाल, भवानी सिंह पटानिया, केहर सिंह खांची, गोकुल बूटेल और आरएसए बाली तक सभी के अधिकार और सुविधाएं सीमित कर दी गई हैं। लज्जरी गाड़ियों की

व्यय, शिमला। हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित पंचायत चुनावों को लेकर निर्वाचन प्रक्रिया तेज कर दी गई है। राज्य में पहली अप्रैल तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश की 392 पंचायतों में नई मतदाता सूचियां तैयार करने का निर्णय लिया गया है, जबकि अन्य पंचायतों में विशेष पुनरीक्षण के माध्यम से मौजूदा मतदाता सूचियों को अपडेट किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार हाल ही में 64 पंचायतों के वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने की दिशा में अगला चरण शुरू करने की तैयारी कर ली है। आयोग 22 मार्च

विशेष पुनरीक्षण से अपडेट होंगी पुरानी सूचियां

जिन पंचायतों में वार्डों में बड़ बदलाव नहीं हुआ है, वहां विशेष पुनरीक्षण के तहत मौजूदा मतदाता सूची को आधार बनाया जाएगा। इस दौरान नए मतदाताओं को जोड़ा जाएगा और मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर ने बताया कि परिसीमन का कार्य पूरा होते ही प्रभावित पंचायतों में नई मतदाता सूचियां बनाई जाएंगी, जबकि अन्य पंचायतों में विशेष पुनरीक्षण किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में बूथ स्तर अधिकारियों की अहम भूमिका रहेगी।

से इस प्रक्रिया को शुरू करने पर विचार कर रहा है। उपायुक्त कार्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 20 मार्च तक परिसीमन से संबंधित कार्य पूरा करें, ताकि मतदाता सूची का काम समय पर शुरू हो सके। चुनाव आयोग के पास अप्रैल का केवल एक महीना ही उपलब्ध है, क्योंकि मई में पंचायत चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में इस अवधि के

● **392 पंचायतों में नई मतदाता सूचियां तैयार**
दौरान मतदाता सूची तैयार करना, उसका प्रकाशन, आपत्तियां आमंत्रित करना और उनका निपटारा करना जैसी सभी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। इसके अलावा चुनाव से संबंधित अन्य जरूरी प्रक्रियाओं को भी इसी समयसीमा में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

आरटीआई में जानकारी देने से इनकार बना विवाद

अनंत ज्ञान

ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी उपक्रम एचपीएमसी एक बार फिर पारदर्शिता को लेकर विवादों में फिर गया है। सूचना का अधिकार के तहत मांगी गई महत्वपूर्ण जानकारी देने से इनकार करते हुए निगम ने जिस तरह कानून का हवाला दिया, उसने इसकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले ने न केवल आरटीआई कानून की प्रभावशीलता बल्कि सरकारी तंत्र की जवाबदेही को भी कठघरे में ला खड़ा किया है। राज्य के पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र चौहान ने एचपीएमसी के इस रुख को अनुचित करार दिया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का ईमेल, एमआईएस योजना के तहत सेब खरीद से जुड़े प्रस्ताव, खरीद केंद्रों की कार्यप्रणाली और टेंडर दस्तावेज जैसी जानकारीयें स्पष्ट रूप से आरटीआई के दायरे में आती हैं। ऐसे में इन सूचनाओं को साझा न करना नियमों और पारदर्शिता दोनों के खिलाफ है। मामले की शुरुआत तब हुई जब शिमला के शिलारू निवासी सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता एवं सेब

◆ एचपीएमसी की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल

हाईकोर्ट की राह पकड़ सकते हैं आवेदक

सुर्दे ठकुर ने एचपीएमसी के वकैय को निराशाजनक बताते हुए कहा कि आरटीआई कानून का मूल उद्देश्य शासन में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है, लेकिन यहां उट्टा सूचना को छिपाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सूचना आयोग में लंबे समय से पद खाली होने के कारण वह अपने अधिकारों से सलाह लेकर इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं।

बागवान सुरेंद्र ठकुर ने 30 जनवरी 2026 को नौ बिंदुओं पर जानकारी मांगते हुए आरटीआई आवेदन दायर किया। हालांकि, उन्हें केवल दो बिंदुओं पर ही जानकारी दी गई, जबकि शेष 7 बिंदुओं को आरटीआई के दायरे से बाहर बताकर खारिज कर दिया गया। इस निर्णय को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं और पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है।

भाजपा ने आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की केंद्र की योजनाओं को पहुंचाने पर दिया जोर, कांग्रेस पर साधा निशाना



जिला भाजपा की बैठक में उपस्थित पदाधिकारी व कार्यकर्ता। **अनंत ज्ञान**

अनंत ज्ञान

ब्यूरो, शिमला। जिला शिमला बीजेपी की एक विशेष बैठक जिलाध्यक्ष केशव चौहान की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यालय दीपकमल, चक्कर में आयोजित की गई। बैठक में आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष केशव चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और पार्टी के कार्यक्रमों को बूथ स्तर तक प्रभावी रूप से लागू करने के लिए

बूथ समितियों का गठन किया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे जिला के सभी मंडलों में जाकर पूर्व भाजपा सरकार के विकास कार्यों और केंद्र की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य सुनिश्चित करें। बैठक में पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कार्यकर्ताओं को संवोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के समय शुरू किए गए कई विकास कार्य आज भी अश्रू पड़े हैं और वर्तमान कांग्रेस सरकार केवल

उन पर श्रेय लेने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी सहित कई योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। इस अवसर पर संगठन के ई.पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिनमें संसदीय क्षेत्र प्रभारी अध्यक्ष भरमौरी, प्रदेश सचिव कुसुम सरदेटी, आईटी संयोजक निखिल कुमार सहित अन्य प्रमुख नाम शामिल रहे।

आर्थिक समीक्षा और सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

समग्र रूप से देखा जाए तो यह फैसला सरकार की आर्थिक समीक्षा और सुधार की दिशा में उठाया गया अहम कदम साबित हो रहा है, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था में एक नई सौच को जन्म दिया है। आने वाले दिनों में यह देखा दिलचस्प होगा कि यह पहल केवल प्रतीकात्मक रहती है या वास्तव में शासन के हर स्तर पर सादगी और पारदर्शिता की स्थायी संस्कृति को स्थापित कर पाती है।

वापसी, निजी स्टाफ में कटौती और विशेष सुविधाओं का समाप्त होना अब जमीन पर लागू होता दिख रहा है। देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से ही इस फैसले का असर स्पष्ट होने लगा है। सरकार ने बेतन और भतों में कटौती कर जहां एक ओर खजाने पर पड़ रहे बोझ को कम करने की दिशा में कदम बढ़ाया है,

सादगी से सुशासन की ओर बढ़ता कदम

हिमाचल सरकार का यह निर्णय केवल सुविधाओं में कटौती तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शासन की कार्यशैली में व्यापक बदलाव का संकेत देता है। वीडाईपी कल्चर पर रोक लगाकर सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जनता के संसाधनों का उपयोग जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। इससे न केवल आर्थिक बचत होगी, बल्कि प्रशासन में जवाबदेही भी बढ़ेगी। यदि यह पहल निरंतर जारी रहती है, तो यह राज्य में सुशासन का मजबूत आधार बन सकती है।

◆ लज्जरी सुविधाओं की विदाई से बदला सत्ता का मिजाज

◆ आर्थिक अनुशासन और जवाबदेही की ओर बड़ा कदम

वहीं यह संदेश भी दिया है कि वित्तीय संकट के दौर में सत्ता को खुद उदाररण पेश करना होगा। अनुमान है कि इस फैसले से हर साल करोड़ों रुपये की बचत होगी, जो विकास कार्यों में इस्तेमाल हो सकती है। दूसरी तरफ राजनीतिक मायनों में यह निर्णय दूरगामी असर छोड़ सकता है। जहां एक ओर इसे

वीआईपी कल्चर पर प्रहार के रूप में देखा जा रहा है, वहीं विपक्ष भी इस पर नजर बनाए हुए है। सत्ता के भीतर भी यह संदेश गया है कि अब पद और प्रभाव से ज्यादा जिम्मेदारी और जवाबदेही को महत्व दिया जाएगा। इससे आने वाले समय में अन्य विषयों और संस्थाओं में भी इसी तरह के कदम देखने को मिल सकते हैं।

विधानसभा

बजट सत्र 2026-27



विधानसभा की झलकियां



बजट सत्र में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुक्खू को पुलिस जवान सलामी देते हुए।



बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुक्खू की शिष्टाचार भेंट।



बजट सत्र में शामिल होने से पूर्व विधानसभा पहुंचने पर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, डिप्टी चीफ डिप्टी केवल पटनिया और विधायक तलेन्द्र राजन ने मुख्यमंत्री सुक्खू का स्वागत किया।

राज्यपाल अभिभाषण पर सदन में सकारात्मक बहस

वादों, योजनाओं और वित्तीय स्थिति पर सत्ता-विपक्ष ने रखे अपने-अपने पक्ष, प्रदेश के विकास और योजनाओं पर फोकस

अनंत ज्ञान

सत्यदेव भारद्वाज, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ने लोकतांत्रिक विमर्श को नई दिशा दी। सदन में विभिन्न जनहित से जुड़े विषयों पर गंभीरता से विचार-विमर्श हुआ, जहां सत्ता पक्ष ने अपनी नीतियों और उपलब्धियों को विस्तार से रखा, वहीं विपक्ष ने जनभावनाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास किया। पूरे दिन की कार्यवाही में सकारात्मक बहस के साथ-साथ प्रदेश के विकास, आर्थिक स्थिति और सामाजिक योजनाओं पर व्यापक चर्चा देखने को मिली।

सीएम ने योजनाओं की प्रगति रखी सामने

मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुक्खू ने चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने पूर्व में शुरू की गई योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए उन्हें अधिक प्रभावी और जनोन्मुख बनाया है। उन्होंने हिमकेयर और सहारा जैसी योजनाओं के विस्तृत आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अधिक संख्या में लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई है, जिससे समाज के कमजोर वर्गों को संतुष्ट मिला है।

जयराम ने अभिभाषण पर उठाए सवाल

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कहा कि यह अभिभाषण सरकार के कामकाज का दर्पण होता है, लेकिन इसमें जमीनी स्तर की वास्तविकताओं का पर्याप्त प्रतिबिंब नहीं दिखा। उन्होंने महिलाओं को आर्थिक सहायता, युवाओं के लिए रोजगार और अन्य चुनावी गारंटियों का जिक्र करते हुए कहा कि इन वादों को धरातल पर उतारने की दिशा में और अधिक ठोस प्रयास अपेक्षित हैं।

कटवाल ने गारंटियों के क्रियान्वयन पर दिया जोर

भाजपा विधायक जीतराम कटवाल ने चर्चा के दौरान कहा कि चुनावी घोषणाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कर्मचारियों के हितों का जिक्र करते हुए नियमित वेतन और भत्तों के समय पर भुगतान की आवश्यकता पर बल दिया और सरकार से इन विषयों पर ठोस कदम उठाने की अपेक्षा जताई।

किशोरी लाल ने सरकार की नीतियों को सराहा

कांग्रेस विधायक किशोरी लाल ने सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि जैसे फैसलों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। इन पहलों से किसानों और ग्रामीणों की आय में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है।

प्रकाश राणा ने आर्थिक पहलुओं पर चिंता जताई

भाजपा विधायक प्रकाश राणा ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार को संसाधनों के रतुलित उपयोग पर विशेष ध्यान देना चाहिए, खासकर तब जब पंचायत स्तर पर आधारभूत ढांचे व कर्मचारियों की उपलब्धता पहले से ही चुनौती बनी हुई है। नई इकाइयों के गठन के साथ वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाना समय की मांग है।

कुलदीप राठौर ने आरडीजी मुद्दे पर रखा पक्ष

कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर ने आरडीजी से जुड़े विषय पर अपनी बात रखते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सदन में गंभीरता से विचार किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी पक्ष मिलकर प्रदेश में सुरक्षा और विश्वास का वातावरण मजबूत करने की दिशा में सहयोग करेंगे और संवेदनशील विषयों पर सामूहिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

नारेबाजी, प्रिविलेज मोशन व सदन में संग्राम

विधानसभा में गरजा विपक्ष, चुनावी गारंटियों के नाम पर जनता को किया गुमराह



विपक्ष के नेता नारेबाजी करते हुए।

अनंत ज्ञान

सत्यदेव भारद्वाज, शिमला। प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण बुधवार को उस वक्त सियासी उबाल पर पहुंच गया, जब सदन के भीतर तीखी बहस व बाहर जोरदार नारेबाजी एक साथ देखने को मिली। विपक्ष ने मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन का नोटिस देकर सियासी तूफान खड़ा कर दिया, वहीं विधानसभा परिसर के बाहर विरोध-प्रदर्शन ने माहौल को और ज्यादा गरमा दिया। आरोप, पलटवार और तलख तेवरों के बीच पूरा दिन राजनीतिक संग्राम का अखाड़ा बना रहा।

अनंत ज्ञान

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि चुनावी गारंटियों के नाम पर जनता को गुमराह किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि ओपीएस को छोड़कर कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ और महिलाओं, युवाओं व किसानों से किए गए बड़े-बड़े वादे अब तक धरातल पर नहीं उतर पाए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार घोषणाओं तक सीमित रह गई है, हकीकत में कुछ नहीं बदला।

हमने काम किया, आंकड़े गवाह हैं: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुक्खू ने इन आरोपों पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने सिस्टम को सुधारे और पारदर्शिता लाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय खोले गए भ्रष्टाचार के रास्ते को बंद किया गया है। मुख्यमंत्री ने हिमकेयर और सहारा जैसी योजनाओं के आंकड़े पेश करते हुए दावा किया कि उनकी सरकार ने अधिक लोगों तक लाभ पहुंचाया और प्रदेश के हित में ठोस फैसले लिए।

राज्यों की आर्थिक स्थिति खराब: प्रकाश राणा

भाजपा विधायक प्रकाश राणा ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर सरकार को घेरे हुए कहा कि राज्य की आर्थिक हालत चिंताजनक है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पहले से ही पंचायतों में स्टाफ की कमी है, तो नई पंचायतों के गठन और उनके ढांचे के लिए संसाधन कहाँ से आएंगे। इस मुद्दे पर सदन में तीखी बहस हुई और सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दी मजबूती: किशोरी लाल

कांग्रेस विधायक किशोरी लाल ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती, दूध के समर्थन मूल्य में वृद्धि और अन्य योजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों का लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंच रहा है और विपक्ष केवल गुजनीतिक माहौल बनाने में लगा है। दिनभर चली बहस, आरोपों और जवाबों के बीच साफ हो गया कि हिमाचल का बजट सत्र अब केवल औपचारिक कार्यवाही नहीं, बल्कि सियासी शक्ति प्रदर्शन का बड़ा चमक बन चुका है। आने वाले दिनों में यह टकराव और तेज होने के आसार हैं।

तीन सवारियों के लिए बसें चलाना व्यावहारिक नहीं: मुकेश अग्निहोत्री

अनंत ज्ञान

ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन सियासी गरमाहट और तीखे तेवरों के नाम रहा, जहां सदन के भीतर सवालियों की धार और जवाबों की तलखी साफ नजर आई। दलहौजी के विधायक द्वारा क्षेत्र में बसें की कमी का मुद्दा जोर-शोर से उठाया गया, जिसमें उन्होंने यहां तक कह दिया कि यदि बसें नहीं लगाई जा सकती तो क्षेत्र को जम्मू-कश्मीर में मिला दिया जाए। इस पर उपमुख्यमंत्री ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि तीन सवारियों के लिए बसें चलाना व्यावहारिक नहीं है, हालांकि ट्रायल के तौर पर बसें चलाने का प्रस्ताव रखा गया और स्पष्ट किया गया कि सफल न होने पर इन्हें बंद कर दिया जाएगा। साथ ही चंबा जिले में पहले से संचालित 203 बसें का हवाला देकर सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की, लेकिन विपक्ष इस जवाब से

इलहौजी में बसों की मांग पर सरकार ने रखी अपनी स्थिति विपक्ष असंतुष्ट

संतुष्ट नजर नहीं आया। वहीं धर्मशाला स्थित शहीद स्मारक और वॉर मेमोरियल को लेकर भी सदन में गंभीर चर्चा देखने को मिली। विधायक केवल सिंह पटनिया के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि स्मारक प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक आम लोगों के लिए खुला रहता है और इसके रखरखाव के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि स्मारक परिसर में संग्रहालय को जल्द तैयार कर जनता के लिए खोलने की दिशा में काम चल रहा है। इन मुद्दों के जरिए विपक्ष ने जहां जनसुविधाओं और व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को घेरे की कोशिश की, वहीं सरकार ने जवाबों के माध्यम से अपनी प्रतिबद्धता जताई।

विपक्ष केवल विरोध के लिए विरोध कर रहा है: सीएम सुक्खू

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर लगाया गलत तथ्यों का आरोप, बताया भाजपा की आंतरिक सियासत

अनंत ज्ञान

सत्यदेव भारद्वाज, शिमला। विधानसभा बजट सत्र के दौरान सियासी तापमान उस वक्त और तेज हो गया जब सदन के भीतर शुरू हुई बहस बाहर आकर भी जारी रही। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर लगाए गए आरोपों के बाद मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुक्खू ने मीडिया के सामने आकर तीखा पलटवार किया। उन्होंने विपक्ष पर न सिर्फ गलत तथ्यों को पेश करने का इल्जाम लगाया, बल्कि इसे भाजपा की आंतरिक खींचतान और दबाव की सियासत का नतीजा भी बताया।

सरकार जवाबदेही और जनहित पर कर रही है काम: मुख्यमंत्री

अंत में मुख्यमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि उनकी सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सियासत में इल्जाम और बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन जनता सब देख रही है और सच के साथ खड़े हैं। प्रदेश के विकास और लोगों के भरोसे को बनाए रखना ही सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, और इसी दिशा में पूरी निष्ठा के साथ काम जारी रहेगा।

जनकल्याण योजनाओं से सरकार का मजबूत दावा

असल तस्वीर कुछ और ही है। सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि मौजूदा सरकार ने जनकल्याण को केंद्र में रखकर काम किया है। उन्होंने हिमकेयर और सहारा जैसी योजनाओं पर हुए खर्च का हवाला देते हुए कहा कि पहले की तुलना में कहीं अधिक संसाधन जनता की भलाई पर लगाए जा रहे हैं। साथ ही प्राकृतिक खेती योजना को किसानों के लिए एक नई उम्मीद बताते हुए कहा कि अब फसलों की खरीद शुरू हो चुकी है और इसका सीधा फायदा किसानों तक पहुंच रहा है।

पूर्व सरकार पर पैसा लूटने का गोंडल का आरोप

पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने खाली पड़े सरकारी भवनों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपये खर्च कर ऐसे ढांचे खड़े किए गए जिनका कोई वास्तविक उपयोग नहीं है, और यह सब ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। उन्होंने इसे पैसा लूटने का मॉडल बताते हुए कहा कि

उनकी सरकार प्रदेश की संपदा को किसी भी सूत्र में लूटने नहीं देगी। प्रशासनिक सक्ती का संकेत देते हुए मुख्यमंत्री ने ओडीआई श्रेणी के अधिकारियों पर जल्द कार्रवाई की जांच भी की जाएगी। इसके अलावा कर्मचारियों के ड्रेस कोड को लेकर भी उन्होंने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि केवल शालीन पहनावे की सरलाह दी गई है, कोई अनिवार्यता नहीं थोपी गई।

विधानसभा बजट के सत्र में विपक्ष का हल्ला बोल, प्रिविलेज मोशन से घिरी सरकार

मुख्यमंत्री के तीन साल झूठ में बीते: जयराम

अनंत ज्ञान

ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण का आगाज सियासी तीव्रता और तलख लहजे के साथ हुआ, जहां नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोलते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने जोरदार नारेबाजी और प्रदर्शन कर राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। जयराम ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने पिछले तीन वर्षों में सदन के भीतर और बाहर लगातार असत्य और भ्रामक बयान दिए हैं, जिससे लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ठेस पहुंची है। इसी मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष को नियम 75 के तहत विधेयाधिकार हनन का नोटिस सौंप दिया, जिससे अब इस पूरे प्रकरण पर राजनीतिक बहस और भी तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।

सरकार जनहित के कार्यों के बजाय होर्डिंग्स के जरिए चमका रही छवि

संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता की उम्मीद की जाती है, लेकिन वर्तमान सरकार इन मूल्यों पर खरी नहीं उतर रही। उन्होंने महिला सम्मान निधि योजना को उदाहरण बनाते हुए कहा कि सरकार के दावों और वास्तविक खर्च के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। सरकार जहां 35,687 लाभार्थियों और 7.42 करोड़ रुपये खर्च की बात करती है, वहीं वास्तविक गणना इसके विपरीत तस्वीर पेश करती है, जिससे

यह संदेह पैदा होता है कि लाभार्थियों को पूर्ण लाभ नहीं मिल पाया। इसके साथ ही सुख आश्रय योजना और कृषि से जुड़ी योजनाओं में भी बेहद सीमित लाभार्थियों का आंकड़ा सामने आने से सरकार की नीतियों की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न खड़े हो गए हैं। जयराम ने केंद्र से मिलने वाली आर्थिक सहायता का हवाला देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने हिमाचल को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में अभूतपूर्व मदद दी है, जो पूर्ववर्ती



सरकारों की तुलना में कई गुना अधिक है। इसके बावजूद राज्य सरकार अपनी विफलताओं का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने का प्रयास कर रही है। उन्होंने अपनी सरकार के समय चलाई गई योजनाओं का जिक्र करते हुए दावा किया कि सहारा, हिम केयर, गुग्गी सुविधा व वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाओं के माध्यम से लाखों लोगों को वास्तविक लाभ मिला था, जबकि वर्तमान सरकार की योजनाएं अधूरी रह गई हैं।

अंग्रेजी अध्यापक भर्ती परीक्षा 3 अप्रैल को होगी आयोजित

अनंत ज्ञान ब्यूरो, शिमला। शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने अंग्रेजी अध्यापक (पोस्ट कोड 26002) के 312 पदों को भरने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 3 अप्रैल को आयोजित करने का निर्णय लिया है। परीक्षा के प्रवेश पत्र लगभग एक सप्ताह पहले जारी किए जाएंगे और अभ्यर्थियों को रोल नंबर व परीक्षा केंद्र की जानकारी मोबाइल संदेश के माध्यम से भी दी जाएगी। इन पदों के लिए 3119 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिससे प्रतियोगिता कड़ी मानी जा रही है। आयोग ने विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण भी सुनिश्चित किया है, जिससे सभी वर्गों को अवसर मिल सके। वहीं, असिस्टेंट स्टाफ नर्स (पोस्ट कोड 26004) भर्ती में भी पदों की संख्या 390 से बढ़ाकर 508 कर दी गई है। यह फैसला स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और अस्पतालों में स्टाफ की कमी दूर करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

लोकतंत्र की कक्षा पटनिया ने छात्रों को सदन की कार्यप्रणाली से कराया परिचित

छात्रों ने समझा कानून बनाने का तरीका

अनंत ज्ञान

ब्यूरो, शिमला। पहाड़ों की वादियों में बहती सियासत की रवानी के बीच आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा का माहौल उस वक्त खास बन गया जब चैम्पली स्कूल लकड़बाजार शिमला और सम्भोट तिब्बतियन उच्च पाठशाला शिमला के छात्र-छात्राओं ने बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही को करीब से देखा। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बच्चों ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पटनिया से कौंसिल चैंबर के बाहर मुलाकात की और लोकतंत्र की इस अहम संस्था के कामकाज को जानने की जिज्ञासा प्रकट की।



विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पटनिया छात्रों को सदन की कार्यप्रणाली की जानकारी देते हुए।

कक्षाएं होती हैं, वैसे ही राज्य में अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और हर क्षेत्र से चुना गया प्रतिनिधि विधायक कहलाता है। ये सभी विधायक मिलकर विधानसभा का गठन करते हैं, जहां सरकार अपने कामों का हिसाब देती है और बजट पेश करती है, जिस पर चर्चा के बाद उसे पारित किया जाता है।

एमआईएस भुगतान अटका, 57 हजार से ज्यादा बागवानों के 120 करोड़ फंसे

अनंत ज्ञान

ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बागवानी क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी हकीकत उस वक्त सामने आई जब सदन में प्रस्तुत आधिकारिक दस्तावेजों ने हजारों बागवानों की आर्थिक परेशानी को उजागर कर दिया। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (एमआईएस) के तहत खरीदे गए सेब का भुगतान लंबित होने का मुद्दा जैसे ही सदन में उठा, यह साफ हो गया कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले सेब उद्योग पर गहरा दबाव बन चुका है। बागवानों के 120 करोड़ रुपये अटकने का मामला अब केवल आर्थिक नशे की बल्कि सियासी और नीतिगत सवाल भी खड़े कर रहा है।



बजट सत्र के दौरान सदन में दी गई विस्तृत जानकारी के मुताबिक 57,182 बागवानों को करीब 120 करोड़ 59 लाख रुपये का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। यह राशि मुख्य रूप से

सरकार ने बजट प्रावधान और केंद्र के सहयोग का दिया गरोसा

विधायक राठौर के सवाल पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने दिया जवाब

हिमफेड और एचपीएमसी के माध्यम से लंबित है। उद्योग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने स्वीकार किया कि भुगतान में देरी हुई है और इसे

